Bihar Administrative Service Association

(Registration No-633/2003)

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 39 Date 16.08.2023

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वित्त विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

विषयः— बिहार सरकार द्वारा 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित बिहार प्रशासनिक सेवा के ऐसे पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति की रिक्ति एवं प्रकाशित विज्ञापन की तिथि उक्त नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने से पूर्व तिथि का होने के कारण भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप निर्णय लेते हुए बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने से संबंधित पुनः अनुरोध किए जाने के संबंध में ।

प्रसंगः—

(1) भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.- 57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 (अनुलग्नक 1)

(2) भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training के निर्गत पत्र संख्या

No. 25011 /02 /2021 -AIS -II (Pension), Dated 13.07.2023 (अनुलग्नक **2**)

(3) सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या–1 / पेन– 1001 / 2023–सा0प्र0–14593, दिनांक 01.08.2023

(अनुलग्नक **3**)

(4) बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा किया गया अनुरोध पत्र संख्या 27, दिनांक 12.04.2023

(अनुलग्नक **4**)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों / आदेशों के साथ अनुरोधपूर्वक कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या–1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा आदेश निर्गत हुआ कि दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया जायेगा (अनुलग्नक **5**)। इसी क्रम में दिनांक–01.09.2005 के बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया गया है ।

(2) इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ के अनुरोध पत्र संख्या 27, दिनांक 12.04.2023 द्वारा पूर्व में भी बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा निर्गत उक्त निर्णय के अनुरूप निर्णय लेते हुए पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने का अनुरोध किया गया था ।

(3) सुलभ प्रसंग हेतु पुनः भारत सरकार से निर्गत उक्त पत्र एवं निर्णय तथा बिहार सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के

पदाधिकारियों के संबंध में निर्गत अधिसूचना के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने के निम्नलिखित आधार का उल्लेख किया जाना आवश्यक है :–

(i) बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 03.02.2004 (दैनिक जागरण) (अनुलग्नक 6) एवं दिनांक–05.11.2004 (Times of India) (अनुलग्नक 7) को किया गया था ।

(ii) इस क्रम में दिनांक 03.02.2004 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में 46वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक–31.03.2004 के पूर्व की तथा दिनांक–14.12.2004 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में 47वीं संयुक्त (प्रा0) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका – 6 में न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक–01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए जिसे बाद में 31.12.2004 तक औपबंधिक रूप से कट–ऑफ डेट निर्धारित किया गया ।

(iii) उक्त विज्ञापनों के आधार पर दिनांक–18 जून, 2007 को 46वीं बैच के चयनित पदाधिकारियों की अधिसूचना बिहार गजट (अनुलग्नक–8) में प्रकाशित की गई तथा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक–24.01.2009 (अनुलग्नक–9) को प्रकाशित किया गया ।

(iv) उपरोक्त (अनुलग्नक–6), 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–1 में अधिकतम उम्र सीमा दिनांक–01.08.2000 तथा (अनुलग्नक–7), 47वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका–1 में अधिकतम उम्र की गणना दिनांक–01.08.2001 के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया गया है ।

(v) इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 46वीं एवं 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन, चयन की अधिसूचना तक कहीं भी नई पेंशन योजना से उक्त रिक्तियों को आच्छादित किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है अर्थात उक्त दोनों 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण दिनांक–01.09.2005 के पहले के प्रचलित पेंशन नियमावली के आलोक में हीं विज्ञापन प्रकाशित की गयी है ।

(4) इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या–21, दिनांक–13.07.2021 द्वारा भी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को C.W.J.C. संख्या–10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार (अनुलग्नक–10) वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–03.08.2011 को पारित आदेश :–

It is infact this aspect of matter which wound clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settles by now that old vacancies have to be Government by the old rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can

not be made applicable के आलोक में– "नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों / कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय ", अनुरोध किया गया था ।

(5) नई पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no 57/05/2021-P&PW(B), Dated 03.03.2023 के द्वारा एक अधिसूचना निर्गत किया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22.12.2003 या उसके पूर्व निर्गत हो, लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन 01.01.2004 से लागू नई पेंशन योजना (NPS) के बाद हुई हो, उनको भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित किया जाएगा तथा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके कंडिका 4 में उल्लिखित प्रावधान निम्नवत है :–

The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided the, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e 22.12.2003 and is covered under the National

Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

(6) उक्त अधिसूचना के आलोक में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Personnel and Training के निर्गत पत्र संख्या No. 25011/02/2021-AIS-II (Pension), Dated 13.07.2023 द्वारा सभी राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को अखिल भारतीय सेवा के ऐसे पदाधिकारीगण जिनकी नियुक्ति हेतु रिक्ति एवं विज्ञापन नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होने की तिथि से पूर्व का है, को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में विस्तृत निर्णय एवं दिशा–निर्देश निर्गत किया गया है ।

(7) उपरोक्त निर्णयों के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के आदेश संख्या –1/ पेन– 1001/2023 –सा0प्र0 –14593, दिनांक 01.08.2023 द्वारा दिनांक 22.12.2003 से पूर्व के प्रकाशित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अधिसूचना की तिथि के आधार पर कुल 11 भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों को उक्त लाभ दिए जाने का आदेश निर्गत किया गया है ।

(8) इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि C.W.J.C. संख्या–2312/2022 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार सरकार वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है जो प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक–11) । विदित हो कि इस वाद में मुख्य सचिव, बिहार सरकार, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, प्रधान

सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार लोक सेवा आयोग, महालेखाकार, बिहार एवं अन्य को पक्षकार बनाने पर भी इस वाद में बिहार सरकार की तरफ से मात्र सहायक निदेशक, सामान्य भविष्य निधि के द्वारा प्रतिशपथ पत्र दायर किया गया है जिसमें माननीय विभिन्न न्यायालयों के न्यायादेश एवं भारत सरकार के उक्त निर्णय तथा परिपत्रों को समाहित / संदर्भित नहीं किया जा सका है । उक्त प्रतिशपथ पत्र में मात्र यह उल्लेख किया गया है कि नई अंशदायी पेंशन योजना बिहार सरकार के द्वारा लागू किए जाने के पश्चात उक्त पदधिकारियों की नियुक्ति हुई है इसलिए इन्हें सामान्य भविष्य निधि का खाता संख्या प्राप्त नहीं कराया जा सकता है । स्पष्ट है कि यह विषय नियुक्ति की तिथि नहीं बल्कि रिक्ति एवं विज्ञापन की तिथि नई अंशदायी पेंशन योजना लागू किए जाने से पूर्व का होने की स्थिति में लिए गए भारत सरकार के निर्णय के समनरूप बिहार सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना वांछित है ।

भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र में भी विभिन्न विभागों से विमर्शोपरान्त तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में उक्त निर्णय लिया जाना उल्लिखित है।

(9) उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी बिहार सरकार द्वारा भारत सरकार के द्वारा गठित वेतन आयोगों की अनुशंसा एवं सेवा शर्त्तों से संबंधित विषयों पर भी समनरूप निर्णय लिया जाता रहा है । अतः इस संबंध में यदि बिहार सरकार द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा उक्त वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना से वापस ले लिया जायेगा, इससे समय एवं संसाधन के अपव्यय से बचा जा सकेगा ।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त प्रासंगिक भारत सरकार के अधिसूचना एवं निर्णयों तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के आदेश संख्या –1/ पेन– 1001/2023–सा0प्र0–14593, दिनांक 01.08.2023 के साथ–साथ माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. संख्या – 10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक–03.08.2021 को पारित आदेश के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन (OPS) योजना का लाभ दिए जाने के बिन्दु पर निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक :– यथोपरि ।

विश्वासभाजन,

(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव

(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

No. 57/05/2021-P&PW(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Pension and Pensioners' Welfare

Lok Nayak Bhawan, Khan Market,
New Delhi, the 03rd March , 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Coverage under Central Civil Services (Pension) Rules, in place of National Pension System, of those Central Government employees who were recruited against the posts/vacancies advertised /notified for recruitment, on or before 22.12.2003.

The undersigned is directed to say that consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. 5/7/2003-ECB & PR dated 22.12.2003, all Government servants appointed on or after 01.01.2004 to the posts in the Central Government service (except armed forces) are mandatorily covered under the said scheme. The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and other connected rules were also amended vide Notification dated 30.12.2003 and, after the said amendment, those rules are not applicable to the Government servants appointed to Government service after 31.12.2003.

2. Subsequently, Department of Pension and Pensioners' Welfare in consultation with the Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of Hon'ble Courts, issued instructions vide OM No. 57/04/2019-P&PW(B) dated 17.02.2020 giving one time option to Central Government employees who were declared successful for recruitment in the results declared on or before 31.12.2003 against vacancies which occurred before 01.01.2004 and were covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). There was fixed time schedule for different activities under the aforesaid OM dated 17.02.2020.

3. Representations have been received in this Department from the Government servants appointed on or after 01.01.2004 requesting for extending the benefit of the pension scheme under Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 (now 2021) on the ground that their appointment was made against the posts/vacancies advertised/notified for recruitment prior to notification for National Pension System, referring to court judgments of various Hon'ble High Courts and Hon'ble Central Administrative Tribunals allowing such benefits to applicants.

4. The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel & Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided that, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, **prior to the date of notification for National Pension System i.e. 22.12.2003** and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given **a one-time option** to be covered under the CCS(Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants **latest by 31.08.2023**.

5. Those Government servants who are eligible to exercise option in accordance with para-4 above, but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by the National Pension System.

6. The option once exercised shall be final.

7. The matter regarding coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), based on the option exercised by the Government servant, shall be placed before the Appointing Authority of the posts for which such option is being exercised for consideration, in accordance with these instructions. In case the Government servant fulfills the conditions for coverage under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), in accordance with these instructions, **necessary order in this regard shall be issued latest by 31st October, 2023**. The NPS account of such Government servants shall, consequently, be closed w.e.f. **31st December, 2023.**

8. The Government servants who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021), shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Regarding accountal of the corpus in the NPS account of the Government servant, Controller General of Accounts (CGA) has furnished the following clarification vide letter No. 1(7)(2)/2010/cla./TA III/390 dated 14.11.2019 & I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022:

i. **Adjustment of Employees' contribution in Accounts**: Amount may be credited to individual's GPF account and the account may be recasted permitting up-to-date interest (Authority-FR-16 &Rule 11 of GPF Rules).

ii. **Adjustment of Government contribution under NPS in Accounts**: To be accounted for as (-) Dr. to object head 70 - Deduct Recoveries under Major Head 2071 - Pension and other Retirement benefit - Minor Head 911- Deduct Recoveries of over payment (GAR 35 and para 3.10 of List of Major and Minor Heads of Accounts).

iii. **Adjustment of increased value of subscription on account of appreciation of investments** – May be accounted for by crediting the amount to Govt. account under M.H. 0071- Contribution towards Pension and Other Retirements Benefits 800- Other Receipts (Note under the above Head in LMMHA)

9. ***All Ministries/Departments are requested to give wide publicity to these orders without fail***. The cases of those Government servants who fulfill the conditions mentioned in this O.M. and who exercise option to switch over to the pension scheme under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) may be settled by the administrative Ministries/Departments in accordance with these orders.

10. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure vide ID Note No. 1(7)/EV/2019 dated 05.12.2022 & 07.02.2023 and in consultation with Controller General of Accounts vide their I.D. Note No. TA-3-6/3/2020-TA-III/cs-4308/450 dated 23.12.2022.

11. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

12. Hindi version will follow.

03.03.2023

(Sanjiv Narain Mathur)
Additional Secretary to Government of India

To,

1. All Central Government Ministries / Departments.
2. Department of Expenditure, Ministry of Finance, North Block, New Delhi.
3. C&AG, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
4. Ministry of Railways, Railway Board, for information, New Delhi.
5. Department of Personnel and Training, North Block, New Delhi.
6. Department of Financial Services, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi.
7. AD (OL) for Hindi version.
8. NIC for uploading on Department's website.

अनुलग्नक -2

(A/3)

No.25011/02/2021-AIS-II(Pension)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated 12/07/2023

To
The Chief Secretaries
All State Governments and UTs

Subject: Coverage under All India Services (Death Cum Retirement Benefits) Rules, 1958, in place of National Pension System, of those members of All India Services who were recruited against the posts/vacancies advertised/notified on or before 22.12.2003.

Sir/Madam,

Consequent on introduction of National Pension System (NPS) vide Ministry of Finance Notification No.5/7/2003-ECB&PR dated 22.12.2003, All India Services (Death-Cum-Retirement Benefits) Rules, 1958 and All India Services (Provident Fund) Rules, 1955 were amended vide Notifications dated 07.02.2004 & 17.05.2004 respectively to mandate that the members of All India Services (AIS) appointed on or after 01.01.2004 will be covered under NPS, and that the benefits of the old Defined Benefit Pension Scheme and GPF will not be available to them.

2. Subsequently, on the basis of the judgments of various Hon'ble Courts and Hon'ble CATs allowing benefits of the old Defined Benefit Pension Scheme to Government servants appointed on or after 01.01.2004 against the posts/vacancies advertised for recruitment prior to the notification of NPS (i.e. 22.12.2003), representations have been received in this Department from similarly placed members of AIS requesting extension of benefit of pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958.

3. The matter has been examined in consultation with the Department of Expenditure and it has been decided that **the AIS officers, who have been appointed against a post/vacancy which was advertised/notified for recruitment prior to the date of notification of NPS (i.e. 22.12.2003) and who are covered under NPS on joining Service on or after 01.01.2004, may be granted one-time option to be covered under the provisions of old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958.**

Therefore, members of AIS selected through Civil Services Examination, 2003, Civil Services Examination, 2004 and Indian Forest Service Examination, 2003 are eligible to be covered under these provisions.

4. Further, the members of Service, who prior to joining AIS were selected in a Central Government service which was covered under CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021) or any other similar rules, are also eligible to be covered under the provisions of D/o P&PW O.M dated 03.03.2023 and, hence, are eligible to be granted one-time option to be covered under the provisions of old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958.

It is clarified that the mobility from one service to another is subject to continuous service and technical resignation (as provided in this Department's OM No. 25011/6/2014-AIS(II) dated 04.11.2015).

5. The option exercised by the members of Service in accordance with these instructions shall be placed before the Government of the State on whose Cadre the member of Service is borne. If any clarification is required, a reference may be sent to the Department of Personnel and Training in case of members of Indian Administrative Service; to the Ministry of Home Affairs in case of members of Indian Police Service; and to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change in case of members of Indian Forest Service.

6. This option may be exercised by the concerned members of Service **latest by 30th November, 2023**. The members of Service, who are eligible to exercise the option in accordance with these instructions but who do not exercise this option by the stipulated date, shall continue to be covered by NPS. The option once exercised shall be final.

7. In case the member of Service fulfills the conditions for coverage under AIS (DCRB) Rules, 1958 in accordance with these instructions, **necessary order in this regard shall be issued latest by 31st January, 2024**. The NPS account of such member of Service shall, consequently, be closed with effect from 31st March, 2024.

8. The members of Service who opt for old pension scheme under AIS (DCRB) Rules, 1958, shall be required to subscribe to the General Provident Fund (GPF). Accordingly, the Controller General of Accounts (Department of Expenditure) has clarified the following procedure for accounting of the corpus in the NPS account of the member of Service:-

a. **Adjustment of Employees' contribution** - Amount shall be credited to the individual's GPF account and the account shall be re-casted permitting up-to-date interest (FR 16 and Rule 9 of All India Services (Provident Fund) Rules, 1955).

However, for the period of service under Central government, employee contribution shall first be credited to 8658-Suspense Accounts, 8658.00.101-Pay and Accounts Office Suspense 'Transactions adjustable with Accounts officer (Name of the State Accountant General)' then the same shall be remitted to Accounts Office of concerned State Accountant General maintaining GPF account by relieving PAO Suspense.

b . **Adjustment of Government contribution** - Amount contributed towards NPS by the Central Government shall be credited to the account of the Central Government; and Amount contributed towards NPS by the State Government shall be credited to the account of the State Government.

The portion of the amount representing Government contribution shall be accounted for as (-) debit to object Head 70-deduct recoveries under Major Head 2071-Pension and Other retirement benefit-Minor Head-911 deduct recoveries of over payment - subhead -03- "Moneys remitted by PFRDA (AIS)" (GAR 35 and para 3.10 of list of Major and Minor Heads of Accounts).

c . **Adjustment of appreciation of investments** - The increased value of subscription on account of **appreciation** on investments shall be accounted for by crediting the amount to the Central Government or the concerned State Government account, as the case may be, in the proportion in which the adjustment of Government contribution is finalized. Appreciation of investment shall be accounted for by crediting the amount to Govt. Account under M.H. 0071-Contribution towards Pension and other Retirements Benefits 800-Other Receipts.

9. This issues in consultation with Ministry of Finance, Department of Expenditure *vide* ID Note No.1(7)/E-V/2019 dated 04.07.2023 and with Controller General of Accounts *vide* UO No.TA-3-07001/6/2021-TA-III/cs-6776/236 dated 07.06.2023 and undated UO No.TA-3-07001/6/2021-TA-III/cs-6776/262.

Enclosed: As above.

Yours sincerely,

(Kuldeep Chaudhary)
Under Secretary to Government of India
Tel: 011-2309 4714

Copy to:

i. Joint Secretary (Police-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
ii. Joint Secretary (UTS-I), Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi
iii. Joint Secretary (IFS), Ministry of Environments, Forest & Climate Change, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi
iv. All Central Government Ministries/Departments
v. Office of Controller General Of Accounts, Mahalekha Niyantrak Bhawan, Ministry of Finance, GPO Complex, Block E, Aviation Colony, INA Colony, Delhi-110023
vi. Accountant General in the States and UTs

(Kuldeep Chaudhary)
Under Secretary to Government of India

अनुलग्नक - 3

1/3

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
--आदेश--

पटना-15, दिनांक [illegible]

आदेश संख्या-1/पेन-1001/2023-सा0प्र0-[illegible]/कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के परिपत्र संख्या-25011/02/2021-AIS-III (पेंशन) दिनांक 13.07.2023 के निर्देश के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) के अधिसूचित होने की तिथि (22.12.2003) के पूर्व नियुक्ति हेतु विज्ञापित/अधिसूचित पद/रिक्ति के विरुद्ध 01.01.2004 या उसके बाद की तिथि को नियुक्ति के उपरान्त योगदान के समय निम्नांकित पदाधिकारियों की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) से आच्छादित सेवा को अखिल भारतीय सेवाएं (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियमावली, 1958 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन योजना का आच्छादन प्रदान करते हुए उसके सभी अनुवर्ती लाभ दिए जाते हैं:-

क्र.	पदाधिकारी का नाम	भा.प्र.से. में आवंटित बैच	सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित अधिसूचना की तिथि	केन्द्रीय सिविल सेवा /भा.प्र.से. में योगदान की तिथि		वर्तमान पदस्थापन
				केन्द्रीय सिविल सेवा में योगदान की तिथि	भा.प्र.से. में योगदान की तिथि	
1	श्रीमती पलका साहनी	2004	07.12.2002	—	06.09.2004	संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
2	श्री आर.लक्ष्मणन	2004	07.12.2002	—	06.09.2004	संयुक्त सचिव, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
3	श्री अभय कुमार सिंह	2004	07.12.2002	—	06.09.2004	सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना
4	श्री (डॉ0) वीरेन्द्र प्रसाद यादव	2004	07.12.2002	—	06.09.2004	विशेष सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना
5	श्री मनीष कुमार	2005	29.11.2003	—	22.08.2005	आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा

6	श्री कुमार रवि	2005	07.12.2002	27.12.2004	22.08.2005	सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना
7	श्री दिवेश सेहरा	2005	29.11.2003	–	22.08.2005	सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना
8	श्री कुलदीप नारायण	2005	29.11.2003	–	22.08.2005	संयुक्त सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली
9	श्री बालामुरुगन .डी.	2005	29.11.2003	–	22.08.2005	संयुक्त सचिव, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली
10	श्री संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी	2006	29.11.2003	05.12.2005	29.08.2006	सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
11	सुश्री रंजिता	2013	29.11.2003	22.08.2005	03.09.2012	श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

2. सभी आलोच्य पदाधिकारियों को भविष्य निधि लेखा आवंटित किए जाने हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा विधिवत् कार्रवाई की जाएगी। उक्त लेखा में राशि का संधारण भारत सरकार के परिपत्र संख्या–25011/02/2021-AIS-III (पेंशन) दिनांक 13.07.2023 के अनुसार किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

01.08.23

(रचना पाटिल)

सरकार के विशेष सचिव।

कृ.पृ.ऊ.

अनुलग्नक -4

(1/3)

Bihar Administrative Service Association

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.-9334118192

Sunil Kumar Tiwary
General Secretary
Mob. No.- 9431085120

Vice President
Ajay Kumar
9835737317

Subodh Kumar
7979919465

Joint Secretary
Chandrashekhar Azad
8987044905

Vikash Kumar
7717770977

Treasurer
Shashi Shekhar
9334557086

Memo No 27 Date 12/04/2023

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार सरकार, पटना

विषयः–भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 के आलोक मे बिहार प्रशासनिक सेवा के 46 वीं एवं 47 वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिए जाने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग, बिहार सरकार, पटना के संकल्प संख्या–1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा आदेश निर्गत हुआ कि दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्य कर्मियों को नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया जायेगा (अनुलग्नक I)। इसी क्रम में दिनांक–01.09.2005 के बाद नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी नई पेंशन योजना (NPS) से आच्छादित किया गया है ।नई पेंशन योजना के संबंध में भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi + Office Memorandum no 57/05/2021-P&PW(B), Dated 03.03.2023 के द्वारा एक अधिसूचना निर्गत किया गया है कि वैसे सरकारी कर्मी जिनकी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22.12.03 या उसके पूर्व निर्गत हो, लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार के अधीन 01.01.04 से लागू नई पेंशन योजना (NPS) के बाद हुई हो, उनको भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने हेतु दिशा निदेश जारी किये गये है, जिसके कंडिका 4 मे उल्लिखित प्रावधान निम्नवत है :–

The matter has been examined in consultation with the Department of Financial Services, Department of Personnel &

O/C

Training, Department of Expenditure and Department of Legal Affairs in the light of the various representations/references and decisions of the Courts in this regard. It has now been decided the, in all cases where the Central Government civil employee has been appointed against a post or vacancy which was advertised/notified for recruitment/appointment, prior to the date of notification for National Pension System i.e 22.12.2003 and is covered under the National Pension System on joining service on or after 01.01.2004, may be given a one-time option to be covered under the CCS (Pension) Rules, 1972 (now 2021). This option may be exercised by the concerned Government servants latest by 31.08.2023.

(अनुलग्नक II)

अतः भारत सरकार से निर्गत उक्त पत्र के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को भी पुरानी पेंशन योजना (OPS) से लाभान्वित करने के निम्नलिखित आधार हैं :–

1. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन का प्रकाशन दिनांक 03.02.2004 (दैनिक जागरण) (अनुलग्नक III) एवं दिनांक–05.11.2004 (Times of India) (अनुलग्नक IV) को किया गया था ।

2. इस क्रम में दिनांक 03.02.2004 के दैनिक जागरण समाचार पत्र में 46वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक–31.03.2004 के पूर्व की तथा दिनांक–14.12.2004 को हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में 47वीं संयुक्त (प्रा0) प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका–6 में न्यून्तम शैक्षणिक योग्यता किसी परिनियत विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री दिनांक–01.08.2001 के पहले की होनी चाहिए जिसे बाद में 31.12.2004 तक औपबंधिक रूप से कट–ऑफ डेट निर्धारित किया गया ।

3. उक्त विज्ञापनों के आधार पर दिनांक–18 जून, 2007 को 46वीं बैच के चयनित पदाधिकारियों की अधिसूचना बिहार गजट (अनुलग्नक– V) में प्रकाशित की गई तथा 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक–24.01.2009 (अनुलग्नक– VI) को प्रकाशित किया गया ।

4. उपरोक्त अनुलग्नक– III, 46वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोतिगता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन की कंडिका–1 में अधिकतम उम्र सीमा दिनांक–01.08.2000 तथा अनुलग्नक–IV, 47 संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका–1 में अधिकतम उम्र की गणना दिनांक–01.08.2001 के आधार पर किया जाना स्पष्ट किया गया है ।

5. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट है कि 46वीं एवं 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन, चयन की अधिसूचना तक कहीं भी नई पेंशन योजना से उक्त रिक्तियों को आच्छादित किया जाना स्पष्ट नहीं किया गया है अर्थात उक्त दोनों 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारीगण दिनांक–01.09.2005 के पहले के प्रचलित पेंशन नियमावली के आलोक में हीं विज्ञापन प्रकाशित की गयी है ।

6. इस संबंध में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा अपने पत्र संख्या–21, दिनांक–13.07.2021 द्वारा भी प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार को C.W.J.C. संख्या–10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार (अनुलग्नक–VII) वाद में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–03.08.2011 को पारित आदेश– **It is infact this aspect of matter which wound clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settles by now that old vacancies have to be Government by the old rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable** के आलोक में– "नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किए गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय",अनुरोध किया गया था (अनुलग्नक– VIII)।

7. इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि C.W.J.C. संख्या–2312/2022 बिहार प्रशासनिक सेवा संघ बनाम बिहार सरकार वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किया गया है जो प्रक्रियाधीन है (अनुलग्नक– IX) भारत सरकार द्वारा निर्गत उक्त पत्र में भी विभिन्न विभागों से विमर्शोपरान्त तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में उक्त निर्णय लिया जाना उल्लिखित है।

अतएव इस संबंध में यदि बिहार सरकार द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो बिहार प्रशासनिक सेवा संघ सरकार के इस कदम का स्वागत करेगा। साथ ही इससे उभय पक्षों के समय एवं संसाधन के अपव्यय से भी बचा जा सकेगा।

अतः अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. संख्या–10901/2006 मो0 क्यूमउद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार में दिनांक–03.08.2021 को पारित आदेश एवं भारत सरकार के Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions Department of Pension and Pensioners Welfare, New Delhi के Office Memorandum no.-57/05/2021-P&PW (B), Dated-03.03.2023 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधानों के अधीन पुरानी पेंशन (OPS) योजना का लाभ दिए जाने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक :– यथोपरि ।

विश्वासभाजन

6/4/23
(सुनील कुमार तिवारी)
महासचिव,

6/4/23
(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष,

अनुलग्नक - 5

अनुलग्नक - I

1/2

परिशिष्ट - I

परिशिष्ट I

संचिका संख्या- वि0(27)पे0फो0-53/04 - 1764

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक- 31. 8. 2005

संकल्प

विषय:- दिनांक 01.09.2005 एवं उसके बाद नियुक्त राज्यकर्मियों के लिए नयी अंशदायी पेंशन योजना।

राज्य सरकार द्वारा समय समय पर, लिये गये निर्णयों के आलोक में सम्प्रति राज्यकर्मियों को केन्द्र सरकार के कर्मियों के अनुरूप वेतनमान, भत्ता, सेवानिवृत्ति की आयु आदि की सुविधायें अनुमान्य है।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय प्रभाग, नई दिल्ली के पत्रांक-05/07/2003 ई0सी0बी0 पी0 दिनांक-22.12.2003 द्वारा भारत सरकार के अधीन दिनांक-01.01.2004 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए वर्तमान में प्रचलित पेंशन योजना के स्थान पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई है। तत्संबंध भारत सरकार के द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए प्रख्यापित अंशदायी पेंशन योजना के सदृश्य राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत दिनांक-01.09.2005 के प्रभाव से अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसका नाम "बिहार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना-2005" होगा।

3. इस संकल्प में निहित प्रावधान वैसे सरकारी सेवकों के मामले में लागू होंगे जिनकी नियुक्ति राज्य सरकार के अधीन दिनांक-01.09.2005 को या उसके बाद हुई हो, परन्तु उक्त प्रावधान संविदा, लोक उपक्रमों एवं स्वायत्त संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर आये कर्मियों, दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मियों तथा पुनर्नियुक्त कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।

4. दिनांक-01.09.2005 या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन विपत्र से मूल वेतन+अनुमान्य जीवन यापन भत्ता के योग की 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी।

5. योजनान्तर्गत संबंधित कर्मियों के अंशदान की कटौती उनके योगदान के अगले माह से प्रारम्भ होगी, अर्थात् यदि सितम्बर, 2005 में किसी ने योगदान किया हो तो अंशदान की कटौती अक्टूबर, 2005 के वेतन से प्रारम्भ होगी।

6. योजना प्रवृत्त होने की तिथि 01.09.2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मियों के मामलों में वर्तमान में लागू सामान्य भविष्य निधि तथा बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, अर्थात सामान्य भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत अंशदान की कटौती नहीं की जायेगी।

7. योजनान्तर्गत अंशदान की कटौती तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये अंशदान संबंधी लेखा का संधारण तत्काल भविष्यनिधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा किया जायेगा तथा भविष्य निधि निदेशालय/कार्यालय द्वारा नई अंशदायी पेंशन योजना के अधीन अंशदान की कटौती के लिए एक लेखा संख्या आवंटित की जायेगी।

8. नई पेंशन योजनान्तर्गत संबंधित कर्मी की सेवानिवृत्ति के समय सेवाकाल में संचित निधि की 40(चालीस) प्रतिशत राशि अनिवार्य रूप से वार्षिकी खरीदने (आई0 आर0 डी0 ए0 नियंत्रित जीवन बीमा कम्पनी से) के लिए कटौती कर ली जायेगी जिससे सरकारी कर्मचारी तथा उस पर आश्रित उसके माता-पिता तथा पति-पत्नी के जीवन यापन हेतु पेंशन की व्यवस्था की जायेगी तथा शेष 60(साठ) प्रतिशत राशि एक

\Server2000\e\pension_sic\sankalp05

सेवानिवृत्त सरकारी सेवक को भुगतान कर दी जायेगी ।

9. इस योजना के कार्यान्वयन के संबंध में अलग से विस्तृत आदेश निर्गत किये जा रहे हैं ।

10. जब तक पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण गठित नहीं हो जाता है, तबतक कर्मियों तथा अंशदान की राशि लोक लेखा में रखी जायेगी तथा इस पर सामान्य भविष्य निधि की दर से ब्याज देय होगा ।

11. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्यरत बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय आदि जहाँ राज्य सरकार के कर्मियों की भांति पेंशन की सुविधा उपलब्ध है को इस नई अंशदायी पेंशन योजना को अनिवार्य रूप से लागू किये जाने हेतु निदेशित किया जाता है ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाये

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

पी0 एन0 नारायणन, 31/8/5
वित्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- पें0(27) [illegible]-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पी0 एन0 नारायणन, 31/8/5
वित्त आयुक्त ।

ज्ञापांक- पें0(27)[illegible] 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभाग, सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी क्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक/निबंधक उच्च न्यायालय पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/सभी समाहर्त्ता/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी समादेष्टा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भगत चौधरी, 31/8/05
उप सचिव ।

ज्ञापांक- पें0(27)[illegible]-53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि- संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन, पंत भवन, पटना/सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

भगत चौधरी 31/8/05
उप सचिव ।

ज्ञापांक- पें0(27)[illegible] 53/04-1964 पटना, दिनांक- 31.8.2005

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि उक्त संकल्प की 1000 प्रति मुद्रित कर वित्त विभाग (पेंशन कोषांग) को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाए ।

भगत चौधरी, 31/8/05
उप सचिव ।

\Server3000\e\pension_sec\sankalp05

अनुलग्नक -6

~~अनुलग्नक - III~~ ~~Annexure-[illegible]~~

(11)

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

[illegible]

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

[illegible]

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

[illegible]

Certified
[illegible signature] 3/1/18
Section Officer
Bihar Public Service Commission
PATNA

[illegible signature]
3-02 [illegible]

~~अनुलग्नक IV~~ अनुलग्नक -7

(17)

बिहार लोक सेवा आयोग

15 जवाहर लाल नेहरू मार्ग (बेली रोड) पटना - 800001

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा

(27)

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

47वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र

परिशिष्ट - 'क'

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

परिशिष्ट - 'ख'

(उपस्थिति पत्रक)

Times of India - 05-11-2004

Certified
Section Officer
Bihar Public Service Commission
PATNA

अनुलग्नक - 8

अनु. ... - V - Annexure-2 Series

(13)

(1/2)

रजिस्टर्ड नं० पी० टी०-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

[illegible]

पटना, [illegible] 2007

(सं० पटना [illegible])

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

[illegible] 2007

सं०- [illegible] बिहार लोक सेवा आयोग की [illegible] संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर [illegible] निम्नलिखित [illegible] अभ्यर्थियों को [illegible] शर्तों के अधीन वेतनमान [illegible] बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए [illegible] परीक्षाधीन उप-समाहर्ता 6500-10,500/- [illegible] के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. [illegible] परीक्षाधीन उप-समाहर्ता [illegible] जिलों में व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु [illegible] किया जाता है :-

क्रम सं०	नाम	मेधा क्रमांक	आरक्षण कोटि	व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
1	2	3	4	5
1	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	पटना
2	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	पूर्णिया
3	श्री [illegible]	12	सामान्य	नालन्दा
4	श्री [illegible]	13	सामान्य	[illegible]
5	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	[illegible]
6	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	[illegible]
7	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	मुंगेर
8	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	कटिहार
9	श्री [illegible]	9	सामान्य	[illegible]
10	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	[illegible]
11	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	[illegible]
12	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	गया
13	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	[illegible]
14	श्री [illegible]	[illegible]	सामान्य	[illegible]

2/2

14

क्रम सं०	नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	आरक्षण स्थिति	व्यावहारिक प्रशिक्षण हेतु आवंटित जिला
1	2	3	4	5
15	श्रीमती किरण सिंह	26	सामान्य	औरंगाबाद
16	श्री मुकेश कुमार	27	सामान्य	सारण (छपरा)
17	श्री सुधीर कुमार	29	सामान्य	लखीसराय
18	श्री परमानन्द [illegible]	30	सामान्य	गया
19	श्री मो० आफताब अहमद	31	सामान्य	गोपालगंज
20	श्री प्रभात चन्द्र	32	सामान्य	सीवान
21	श्री विवेक [illegible]	35	पिछड़ी जाति	शेखपुरा
22	श्री प्रिय रंजन राजू	36	अत्यन्त पिछड़ी जाति	पश्चिम चम्पारण
23	श्री अमरेन्द्र कुमार	40	पिछड़ी जाति	मुजफ्फरपुर
24	श्री मो० नुरुल ऐन	43	अत्यन्त पिछड़ी जाति	सीतामढ़ी
25	श्री मनोज कुमार [illegible]	45	पिछड़ी जाति	शिवहर
26	श्री विनोद कुमार	46	पिछड़ी जाति	पूर्वी चम्पारण
27	श्री मो० [illegible] हुसैन	47	अत्यन्त पिछड़ी जाति	वैशाली
28	श्री वीरेन्द्र कुमार	49	अत्यन्त पिछड़ी जाति	दरभंगा
29	श्री राजेश कुमार	51	पिछड़ी जाति	पटना
30	श्री प्रभात कुमार	53	अत्यन्त पिछड़ी जाति	मधुबनी
31	सुश्री रेणु कुमारी	56	पिछड़ी जाति महिला	सहरसा
32	श्री शाहनवाज अख्तर निजामी	57	अत्यन्त पिछड़ी जाति	समस्तीपुर
33	श्री मो० मुनव्वर [illegible]	61	अत्यन्त पिछड़ी जाति	मुंगेर
34	श्री नुरुल हक [illegible]	62	अत्यन्त पिछड़ी जाति	बेगूसराय
35	श्री प्रवेश कुमार	63	अत्यन्त पिछड़ी जाति	सुपौल
36	श्री मुकेश कुमार	70	अनुसूचित जाति	मधेपुरा
37	श्री विश्वनाथ पासवान	137	अनुसूचित जाति	पूर्णियाँ
38	श्री [illegible]	169	अनुसूचित जाति	अररिया
39	श्री नीरज कुमार	187	अनुसूचित जाति	किशनगंज
40	श्री मनोज कुमार	197	अनुसूचित जाति	कटिहार
41	सुश्री प्रियदर्शिनी अनामिका	199	अनुसूचित जाति	मुजफ्फरपुर
42	श्री सुधीर कुमार	206	अनुसूचित जाति	भागलपुर

उपर्युक्त औपबंधिक नियुक्तियाँ निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाती है:-

(क) स्थायी/ आस्थायी पते का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन संबंधी कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से [illegible] की जा सकती है।

(ख) समर्पित प्रमाण-पत्रों/ [illegible] शैक्षणिक/ अन्य प्रमाण पत्रों की सम्पुष्टि में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिफल प्राप्त होता [illegible] उनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जायेगी।

(ग) औपबंधिक [illegible] सभी परिक्ष्यमान उप-समाहर्त्ता अपने नाम के सामने उल्लिखित जिले में पत्र प्राप्ति [illegible] के अन्दर योगदान [illegible] के एक प्रति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेंगे। [illegible] योगदान तब तक स्वीकृत नहीं हो सकेगा, यदि उनके द्वारा मूल स्नातक डिग्री [illegible] [illegible] आवासीय प्रमाण-पत्र, जिसे पूर्व में विभाग को समर्पित नहीं किया गया हो, [illegible] प्रतीत जिला पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि मूल प्रमाण-पत्र देखकर संतुष्ट हो [illegible] द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति जाँच हेतु विभाग को [illegible] [illegible] भेजी जायेगी।

(घ) [illegible] अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र [illegible] जा रहा है। [illegible] नियुक्ति पत्र प्रस्तुत न किये जाने पर कोई योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
[illegible],
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 378-571+200-डी० टी० पी०।

अनुलग्नक-9

अनुलग्नक-IV

(15)

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फल

47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अंतर्गत साक्षात्कार हेतु चयनित कुल 224 उम्मीदवारों की मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार दिनांक 12.01.2009 से 14.01.2009 की अवधि में सम्पन्न हुआ। उक्त मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में चार उम्मीदवार, अनुक्रमांक 129040, शम्भु कुमार सिंह, अनुक्रमांक 129860, हरिश्चंद्र नाथ, अनुक्रमांक 130612, संजय कुमार एवं अनुक्रमांक 149920, संजय भारती ने भाग नहीं लिया। शेष 220 उम्मीदवारों की उनकी (मुख्य) लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों की जोड़ के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त क्रमिक मेधा सूची के अधीन, राज्य संवर्ग/सेवाओं के लिए उनके द्वारा इंगित अधिमान–क्रम को प्रश्रय देते हुए चयनित सेवा के लिए उनकी सुयोग्यता तथा आरक्षण रोस्टरवार रिक्त पद–उपलब्धता के अनुसार निम्नांकित उम्मीदवारों को इंगित राज्य संवर्ग/सेवा में नियुक्ति हेतु सफल घोषित किया जाता है–

क्रम सं.	अनुक्रमांक	नाम	मेधा क्रमांक	आवंटित आरक्षण रोस्टर बिन्दु
(1) बिहार प्रशासनिक सेवा:				
1.	134330	हरिशंकर प्रसाद कुशवाहा	6	सामान्य
2.	107027	राजेश्वरी पाण्डेय	6	सामान्य
3.	110983	कुमार प्रशान्त	7	सामान्य
4.	124075	नीरज कुमार दास	8	सामान्य
5.	142539	शम्भु नाथ	9	सामान्य
6.	103574	किशोर कुमार	10	सामान्य
7.	128331	संजीव कुमार	11	सामान्य
8.	118130	दुर्गेश कुमार	12	सामान्य
9.	102012	चन्द्रशेखर आजाद	13	सामान्य
10.	116308	राकेश कुमार	14	सामान्य
11.	163352	गिरिजेश कुमार	15	सामान्य
12.	150049	अनिल कुमार तिवारी	16	सामान्य
13.	167767	देवेन्द्र प्रताप शाही	17	सामान्य
14.	147319	हरि शंकर	18	सामान्य
15.	102326	मधु कान्त	20	सामान्य
16.	100254	शैलेश चन्द्र दिवाकर	21	सामान्य
17.	164093	नीतू सिंह	22	सामान्य
18.	151005	रामानुज प्रसाद सिंह	23	सामान्य
19.	103584	अखिलेश कुमार	26	पिछड़ा वर्ग
20.	100604	अमिताभ कुमार गुप्ता	28	पिछड़ा वर्ग
21.	130314	सुरेन्द्र कुमार कलबेला	29	पिछड़ा वर्ग
22.	162363	संजय कुमार सिंह	33	पिछड़ा वर्ग
23.	156933	अशोक कुमार गुप्ता	35	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
24.	105134	अनु कुमार	43	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
25.	130441	प्रतिमा सिन्हा	48	पिछड़ा वर्ग की महिला
26.	113825	बुद्ध प्रकाश	52	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
27.	116220	कयूम अंसारी	64	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
28.	132587	उत्तम कुमार	65	पिछड़ा वर्ग (विकलांग)
29.	123078	शफिकुल्लाह अंसारी	74	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
30.	140103	मुकेश कुमार	78	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
31.	132304	हरेन्द्र राम	104	अनुसूचित जाति
32.	112104	कुमार धनन्जय	128	अनुसूचित जाति
33.	127912	अरुण प्रकाश	153	अनुसूचित जाति
34.	125401	बिमल आनन्द	165	अनुसूचित जाति
35.	136005	शशि भूषण किशोर	168	अनुसूचित जाति
36.	156491	नवीन कुमार	171	अनुसूचित जाति
(2) बिहार आरक्षी सेवा:				
37.	117565	उमेश कुमार	1	सामान्य
38.	133777	अरुण कुमार झा	2	सामान्य
39.	155171	राजेश कुमार सिंह प्रभाकर	3	सामान्य
40.	126258	नय रंजन हरगदे	4	सामान्य
41.	120365	मनोज कुमार	56	अनुसूचित जाति
(3) वाणिज्यकर अधिकारी:				
42.	108275	नरेन्द्र प्रताप सिंह	24	सामान्य
43.	171678	मुकेश कुमार	25	सामान्य
44.	127821	शशिकान्त चतुर्वेदी	27	सामान्य
45.	158434	रवि रंजन आलोक	50	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
46.	143800	संजय कुमार	185	अनुसूचित जाति
(4) अवर निबंधक:				
47.	102259	राजेश कुमार सिंह	30	सामान्य
48.	121836	ऋषि कुमार सिन्हा	32	सामान्य
49.	100061	प्रमोद कुमार	39	पिछड़ा वर्ग
50.	164957	संजय कुमार	44	पिछड़ा वर्ग
51.	106170	मनोज कुमार	80	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
52.	112074	मदन कुमार	172	अनुसूचित जाति
(5) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी:				
53.	101014	कुसुम चन्द्र वर्मा	31	सामान्य
54.	130083	प्रदीप कुमार सिंह	34	सामान्य
55.	142420	राजेश कुमार	36	सामान्य
56.	113120	कुन्दन लाल	45	सामान्य
57.	119462	शैलेन्द्र कुमार	47	सामान्य
58.	133091	विजयानन्द राकेश	193	अनुसूचित जाति
59.	156714	घनश्याम रविदास	194	अनुसूचित जाति
(6) श्रम अधीक्षक:				
60.	127127	राकेश ओझा	37	सामान्य
61.	140208	विजय कुमार अशोक	41	सामान्य
62.	102658	जयकर लाल प्रभाकर	46	सामान्य
63.	108571	रणजीत कुमार झा	49	सामान्य
64.	123289	शिव भूषण मिश्रा	51	सामान्य
65.	149004	मनोज कुमार	53	सामान्य
66.	149150	रुद्रेश कुमार मधुकर	54	पिछड़ा वर्ग
67.	164723	राजेन्द्र कुमार	91	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
68.	103416	मोती लाल	115	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
69.	164997	धर्मेश्वर चौपाल	150	अनुसूचित जाति
70.	105692	अरुण पासवान	195	अनुसूचित जाति
(7) सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ:				
71.	120733	राजीव कुमार सिंह	38	सामान्य
72.	171217	वीरेन्द्र शर्मा	42	सामान्य
73.	120679	मननाथ प्रसाद	60	पिछड़ा वर्ग
74.	103208	मो. इरफान आलम	89	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
75.	127524	राज कुमार	96	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
76.	112272	बबलू राजा	99	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
77.	145005	कुमार स्नेहलता	107	पिछड़ा वर्ग की महिला
78.	151078	[illegible]	120	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
79.	149459	अरुण कुमार	121	अत्यंत पिछड़ा वर्ग
80.	148700	[illegible]	131	पिछड़ा वर्ग की महिला
(8) सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी:				
81.	158658	नरेन्द्र कुमार	55	सामान्य
82.	111878	अभिताभ अंकित	57	सामान्य
83.	111982	मनोज कुमार	58	सामान्य
84.	130748	सुरेन्द्र नारायण सिंह	59	सामान्य
85.	117512	दिलीप कुमार	61	सामान्य
86.	168788	अनिल कुमार	63	पिछड़ा वर्ग
87.	125486	रविन्द्र कुमार दिवाकर	182	अनुसूचित जाति

2. उपर्युक्त 220 उम्मीदवारों में से अनुक्रमांक 111581, नीलाम कृष्ण (मेधा क्रमांक–19) एवं अनुक्रमांक 111822, शशि शेखर (मेधा क्रमांक–40) द्वारा सेवाओं के लिए दिये गये आंशिक अधिमान–क्रम के अधीन उनके उक्त मेधा–क्रमांक तक तदनुसार रिक्ति शेष नहीं रही, जिस कारण उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की जा सकी है; उक्त दो उम्मीदवारों ने उक्त सभी अन्य सेवाओं/पदों के लिए अपना अधिमान–क्रम अंकित नहीं किया है।

3. परीक्षाफल के मुद्रण की किसी त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेवार नहीं होगा।

4. उपर्युक्त परीक्षाफल आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर देखा जा सकता है।

5. उपर्युक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के लब्धांक दिनांक 30.01.2009 से आयोग के उक्त वेबसाईट पर प्रकाशित रहेंगे एवं तदनुसार ही इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

तिथि: 24 जनवरी, 2009

Certified
Section Officer
Bihar Public Service Commission
PATNA

24/1/09
उप सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना

आसूचना-VII

Annexure '04'

(18)

Bihar Administrative Service Association

North of Income Tax Golambar, Nehru Marg, Patna 800001
(Registration No-663/2001)
Website: basabihar.com, E-mail id: infobasa1@gmail.com

Shashank Shekhar Sinha
President
Mob. No.- 9334118192

Anil Kumar
General Secretary
Mob. No.- 9431409463

ice President
d. Moeezuddin
9304951290

Ajay Kumar
9835737317

oint Secretary
ubodh Kumar
7979919465

Gopal Sharan
8210342042

Treasurer
l Kumar Tiwary
9431085120

int Treasurer
Mona Jha
9430881025

Memo No 21 Date 13.07.2021

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन-विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

विषयः– 46वीं एवं 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मुहैया कराने के संबंध में।

प्रसंगः– (1) CWJC No-10901/2006 मो० कयुमुद्दीन अंसारी बनाम बिहार सरकार वाद में दिनांक–03.08.2011 को पारित आदेश।
(2) अधोहस्ताक्षरी का पत्रांक 09 दिनांक 15.01.2020 (छायाप्रति संलग्न)

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी हैं एवं वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन दिनांक–01.09.2005 के बाद लागू नई पेंशन योजना से आच्छादित है जबकि 47वीं बैच के पदाधिकारियों को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के प्रावधान अर्थात् पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना चाहिये जिसके निम्नलिखित आधार है;

2. बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 47वीं बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियो हेतु चिन्हित रिक्तियों के विरूद्ध विज्ञापन का प्रकाशन (छायाप्रति संलग्न) 05.11.2004 को किया गया था। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 14.12.2004 निर्धारित की गयी थी।

3. इस क्रम में दिनांक–14.12.2004 को हिन्दुस्तान दैनिक जागरण सहित अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापन (छायाप्रति संलग्न) प्रकाशित किया गया, जिसमें उल्लिखित है कि 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के क्रम संख्या–6 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को परिभाषित करते हुए आवेदन जमा करने की तिथि को दिनांक–31.12.2004 तक बढ़ाया गया था।

(19)

4. उक्त विज्ञापन के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक–24.04.2005 को 47वीं संयुक्त (प्रा०) प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गयी तथा इसका परीक्षा फल (छायाप्रति संलग्न) बि.लो.से. आयोग द्वारा 16.12.2008 को घोषित किया गया।

5. 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अन्तर्गत साक्षात्कार/मौखिक परीक्षा 12.01.2009 से 14.01.2009 तक आयोजित की गयी एवं अंतिम परिणाम (छायाप्रति संलग्न) 24.01.2009 को घोषित की गयी।

अतः उक्त साक्ष्य के अनुसार निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते है;

(क) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन वर्ष 2001 के आधार मानकर की गई है।

(ख) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता हेतु प्रारम्भिक परीक्षा 24.04.2005 को आयोजित की गई है।

(ग) 47वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार प्रशासनिक सेवा हेतु नियोजना मुख्य सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 430 दिनांक 06.05.2005 के आलोक में की गयी है।

6. इस प्रकार स्पष्ट है कि 47वीं संयुक्त बिहार प्रतियोगिता परीक्षा हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के पदों की रिक्तियाँ नई पेंशन योजना अर्थात 01.09.2005 के पहले लागू नियमावली के आलोक में की गयी है। इसी प्रकार का समदृश्य मामला 46वीं बैच के पदाधिकारी का भी है।

7. इसी बीच माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC सं0–10901/2006 में कयामुद्दीन अंसारी एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में दिनांक 03.08.2011 को निम्नलिखित आदेश (छायाप्रति संलग्न) पारित है;

"It is infact this aspect of matter which wound clinch the issue in favour of the petitioners in as much as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules can not be made applicable."

8. उक्त न्याय निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि नई पेंशन योजना लागू होने की तिथि के पूर्व नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त किये गए पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया जाय।

9. अतः अनुरोध है कि उक्त न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग, बिहार सरकार का संकल्प सं0 1964 दिनांक 31.08.2005 की कंडिका 3 एवं कंडिका 6 में उल्लिखित प्रावधानों को विलोपित एवं क्षांत करते हुए 01.09.2005 के पूर्व प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर नियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के 46वीं एवं 47वीं बैच के पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए मंत्रीस्तरीय निर्णय लेने की कृपा की जाय।

अनुलंग्नकः–यथोपरि।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)
महासचिव

विश्वासभाजन

(शशांक शेखर सिन्हा)
अध्यक्ष

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
CIVIL WRIT JURISDICTION CASE No.10901 of 2006

1. Md.Kayumuddin Ansari, son of Shri Rahmat Ali Ansari, resident of Latif Market, Chokhandi Road, P.S. Sasaram, Sasaram
2. Krishna Kumari, D/o Shri Ramji Prasad Gupta, resident of village Sikarhgarh Tola (L.C.T. Ghat Road), near Mishra Medical Hall, P.O. + P.S. Kahalgaon, District Bhagalpur
3. Arun Kumar, son of Shri Parasnath Prasad, resident of Khajpura Ambedkar Path, P.O. B.V.College, P.S. Shastrinagar, Bailey Road, Patna- 800014
4. Seema Kumari, D/o Shri Ajeet Kumar Yadav, resident of village + P.O. Latra, P.S. Nawgachhiya, District Bhagalpur
5. Shashibhushan Kumar Sinha, son of Shri Janardan Prasad, resident of village Manara, P.S. Noorsarai, District Nalanda
6. Kiran Kumari, D/o Shri Jagdish Prasad, resident of village Bishnupur, P.O. Ranipar, P.S. Noorsarai, District Nalanda
7. Satish Kumar, son of Shri Jaleshwar Prasad Singh, resident of Health Institute Road, Beur, P.S. Gardanibagh, Anisabad, District Patna- 800002
8. Surendra Ram, son of late Ramdeni Ram, resident of village Mataya, P.O. + P.S. Madhopur Ram, District Vaishali
9. Jitendra Kumar Sinha, son of Shri Ramprit Prasad, resident of village Ratan, P.S. Atari, District Gaya

... Petitioners

Versus

1. The State Of Bihar through the Chief Secretary, Govt. of Bihar, Patna
2. The Commissioner, Finance, Govt. of Bihar, Patna
3. The Commissioner cum Secretary, Health Services, Department of Health, Govt. of Bihar, Patna
4. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Contributory Provident Fund, Bihar, Patna
5. The Additional Secretary, Health and Family Welfare, Department, Vikash Bhawan, Patna
6. The State Drugs Controller, Directorate Health Services, Vikash Bhawan, Patna
7. The Bihar Public Service Commission, Bihar, patna, through its Secretary

... Respondents

For the petitioners : Mr. Mithilesh Kumar Rai, Adv.
For the State : Mr. Bijay Kumar Pandey, A.C. to G.P.20
For the BPSC : Mr. Sanjay Pandey, Adv.

5. 3.8.2011 Having heard counsel for the parties as with regard to the following relief:

"That this is an application for issuance of a writ in the nature of mandamus directing and commanding

WEB COPY NOT OF FILE

2/7

21

the respondent authorities not to give effect to letter no. 690 dated 3.3.2006, issued under the signature of the Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, so far as it relates to the petitioners, which is said to have been pursuant to Gazette notification bearing No. 614 dated 18.11.2005, whereby and whereunder it speaks of the fact that the persons having been appointed on 1.9.2005 or thereafter, shall have to be a member of the newly contributory find scheme, as also to treat the petitioner to have been appointed prior to 1.9.2005 for the purposes of application of the service condition in regard to pension."

WEB COPY NOT OFFICIAL

this Court is of the considered opinion that as the Bihar Public Service Commission had ultimately recommended the names of the petitioners on 25.6.2004 in continuation to the earlier recommendation of 41 candidates vide its letter No. 39 dated 12.5.2003 by making it clear that the name of the petitioners shall be placed below the 40th candidate and above 41st candidate, there should have been no difficulty for the Government to allow the benefit of old pension scheme which was prevalent at the time of appointment of the 41st candidate.

The issue in fact becomes very simple if it is taken into account that by one advertisement No. 2 of 2000 the post of Drug Inspector were advertised but when the result of the same was published in the year 2001 the petitioners were shown to have been unsuccessful in the written test, whereas the Commission had recommended the name of the other 41 persons in the year 2003 after conducting interview and preparing selection list. The

petitioners and the similarly situated ? persons alike the petitioners thereafter had assailed the result and recommendation of the Commission on a ground that they were illegally edged out without following the Government's own scheme and policy as with regard to lowering qualifying mark in the written test for the Backward categories. This Court in its judgment dated 16.5.2002 in L.P.A.No. 1283 of 1999 and its analogous cases infact had upheld such claim and had directed the Commission to re-determine the merit list on the basis of qualifying marks prescribed under the statutory Rules. The Commission thereafter had made such exercise and sent its recommendation on 25.6.2004 wherein the names of 11 persons including the petitioners were recommended and it was clarified that their place of seniority will be below Sl.No. 40 and above Sl.No. 41 of the earlier list dated 12th May, 2003. Consequently such recommendation of the petitioners had not only been accepted by the Government but an offer of appointment was also issued to them on 11.8.2005 communicating that the Government had already decided them to appoint on the post of Drug Inspector and as such they should give their option of three districts for their respective place of posting. While all these things had already happened, the Government had taken a decision that from 1.9.2005 any person appointed in the Government service will not be entitled to the existing policy of pension being paid to them under the Bihar Pension Rules and they would be governed by a new contributory pension scheme framed by the government. Eventually when the petitioners were

WEB COPY NOT OFFICIAL

also appointed by a notification dated 28.11.2005 they were also deprived of the benefit of pension under old policy and scheme governed by Bihar Pension Rules and they were also coerced to accept the new policy of Contributory Pension Scheme which according to them is less beneficial in comparison to the earlier Scheme. It is with this grievance that this writ application has been filed that as they are senior to the persons appointed on the basis of same advertisement and selection process they cannot be prejudiced in the matter of service condition as was given to other persons including a person below them in the merit list.

WEB COPY NOT OFFICIAL

Learned counsel for the Commission has clarified that the Commission had gone into this exercise and had made its recommendation very clear that the place of the petitioners as per roaster and reservation in view of the direction given by this Court in the judgment dated 16.5.2002 in L.P.A. No. 1823 of 1999, would be below Sl.No.40 of the original list and above 41 of the same list. In fact the Commission has itself placed the revised recommendation dated 25.6.2004 and Mr. Pandey, appearing on behalf of the Commission, has also very fairly produced even the earlier recommendation 12.5.2003, which has been kept on the records of this case. From the simultaneous reading of the two recommendations of the Commission dated 12th May, 2003 and 25.6.2003 it would become absolutely clear that the petitioners will be deemed to be appointee of the same transaction and barring the benefit of payment of salary for the period they had not worked on account of denial of their appointment they were entitled for all

other benefits including seniority to which were extended to other 41 Drug Inspectors appointed earlier in view of the recommendation of Commission in its letter dated 12.5.2003.

In that view of the matter, this Court would find it difficult to accept the submission of the learned counsel for the State who has given only one explanation by way of justification of the Government decision that the petitioners being appointee after 1.9.2005 were to be governed by the new contributory pension scheme. Such submission of learned counsel for the State is based on an arithmetical calculation that since the appointment letter of the petitioners was issued after cutoff date of 1.9.2005 they will be automatically deprived from availing the earlier benefit of pension under Bihar Pension Rules which was given to the appointees of the year 2003. This Court however would fail to understand the logic of such submission, inasmuch as when the petitioners were subjected to same selection process in terms of the same advertisement and ultimately their case was recommended by the Commission in continuation of the same merit list by placing them above a person who was originally recommended and appointed, it would be difficult to accept such justification given by the State Government that the petitioners still will be deprived of the benefit of the old pension scheme because they were appointed after 1.9.2005. It was not the fault of the petitioners that the Commission and/or the Government did not follow its own policy of following its decision regarding lower qualifying marks for the candidates belonging to backward

WEB COPY NOT OFFICIAL

(6/7)

(25)

category and therefore, if the Government and the Commission had to be directed by this Court in the case filed by the similarly situated persons for drawing a fresh merit list, and in such merit list the name of the petitioners had figured above someone who was originally recommended, they cannot be deprived of the benefit which has been given to the originally recommended candidates.

WEB COPY NOT OFFICIAL

It is in fact this aspect of the matter which would clinch the issue in favour of the petitioners inasmuch as it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new Rules coming into force after beginning of process of selection as per old Rules cannot be made applicable. Reference in this connection may be usefully made to the judgment of Apex Court in the case of P. Mahendran Vs. State of Karnataka reported in (1990) 1 SCC 411. Moreover a right to receive pension is condition of service as has been held by the Apex Court in the case of Union of India Vs. Gurnam Singh reported in (1982) 2 SCC 314 and thus to be governed in accordance with the terms and condition of the advertisement and the existing Rules inasmuch he acquires a right to be considered for selection and appointment in accordance with the then existing Rules. This Court would accordingly hold that the petitioners being appointees of the old transaction of Advertisement No. 2 of 2000 in continuation with old appointees of 2003 will be entitled to get the benefit of old pension scheme and they will not be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme coming

into force w.e.f. 1.9.2005. It has to be also kept in mind that even the original appointment letter issued on 26.11.2005 to the petitioners, did not contain any clause and/or condition that they will be governed by the new Contributory Pension Fund Scheme and therefore, the resolution of the Finance Department, contained in Annexure 10 dated 1.9.2005, cannot be made applicable in the case of the petitioners as it was not made part of their service condition also in their appointment letter.

For all these reasons, this application is allowed and the respondents are directed to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the petitioners as was extended to other Drug Inspectors appointed out of the same advertisement and transaction.

(Mihir Kumar Jha,J.)

Surendra/

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुलग्नक – 11

~~4 of 12~~

(19)

Filed through:

Abhay Shanker Singh 29/01/2022

Abhay Shanker Singh, Adv.

AOR No. 01994

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

CWJC No. ..2312..... /2022

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India

AND

In the matter of :-

Bihar Administrative Service Association through its General Secretary Sri Anil Kumar, son of Late Raja Ram Singh, aged about 56 years, Male, having its office at BASA BHAWAN, North of Income Tax Golamber, J.L. Nehru Marg, Patna ---- --- Petitioner

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary, Government of Bihar, Patna
2. The Principal Secretary, Department of Finance, Government of Bihar, Patna
3. The Principal Secretary, General Administration Department, Government of Bihar, Patna
4. The Commissioner, Finance, Government of Bihar, Patna

5. The Joint Commissioner, Accounts Administration, Department of Finance, Government of Bihar, Patna
6. The Bihar State Public Service Commission through its Secretary, Jawaharlal Nehru Road, Patna
7. The Accountant General, Bihar, Patna

--- ---- Respondents

To

Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and his companion Justices at the said Court

Humble application on behalf of the aforesaid petitioner

<u>Most Respectfully Sheweth</u>:

1. That the petitioner Association beseeches indulgence of this Hon'ble Court for the following relief/s:

   (a) For issuance of appropriate writ or writs in the nature of mandamus directing and commanding the respondent authorities to give benefit of old pension scheme under Bihar Pension Rules to the members of the petitioner association who had been appointed under 46th and 47th Batch of Bihar Administrative Service and further not to give effect to Clause 03 and Clause 06 of the Resolution No. 1964 dt. 31.08.2005 of the Finance Department , Govt. of Bihar and to lax the same with respect to them as they had been appointed under 46th and 47th Batch through advertisements published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively, for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff

date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme and thus, they are entitled to old pension scheme and not with the new contributory pension scheme; under which they have been brought arbitrarily and discriminately by the respondent authorities.

(b) For any other relief or reliefs as the Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

2. That the issues of seminal importance raised in this writ petition are as follows:-

i. Whether the members of petitioner association who were appointed in pursuance to advertisements published before 01.09.2005 under 46th and 47th batch for the older vacancies, are not entitled to old pension scheme and the Resolution of the government vide No. 864 dt. 31.08.2005 is not applicable to them?

ii. Whether the members of petitioner association appointed in 46th and 47th batch of the BPSC are being covered under new pension scheme in most mechanical, arbitrary and unreasonable manner?

iii. Whether non-inclusion of members of petitioner association appointed in 46th and 47th batch under the old pension scheme deprive them of their right as guaranteed under Article 14, 16, 21 and 300A of the Constitution of India?

3. That it is stated that the Petitioner is an Association of Bihar State Administrative Service Officers with Registration No. 663/2003 under Societies Registration Act, 1860 and this writ petition is being filed through its General Secretary in representative capacity because the issue raised herein affects all the members of the petitioner Association; so appointed through Advertisement for 46th and 47th Joint Competitive Examinations of BPSC and is of common interest.

4. That it is stated that the advertisement for appointment to the existing older vacancies of posts of Bihar Administrative Service, Bihar Finance Service, Bihar Education Service and Bihar Labour Service (General), Bihar Jail Service, Assistant Recruitment Officers etc. was published in the Hindi Daily Dainik Jagran , Hindustan and as well as English daily Times of India, Patna in February 2004 and 05.11.2004 respectively for 46th and 47th batch of Joint (Preliminary) Competitive Examination (those appointed through this are hereinafter referred as 46th-47th batch officers).

A copy of the aforesaid advertisements published in February 2004 and 05.11.2004 are annexed as Annexure-01 Series.

5. That it is stated that the Preliminary Competitive Examination of the 46th and 47th Batch for older vacancies were held prior to May 2005(24.04.2005) and final results were published on 27.06.2007 and 24.01.2009 respectively.

A copy of the final result of 46th and 47th batch officers so published on 27.06.2007 and 24.01.2009 by BPSC, Patna is annexed as Annexure-2 Series.

6. That in respect of the 46th and 47th Joint Competitive Examination, following facts are pertinent to be considered:

(i) The advertisements were published by the respondent Bihar Public Service Commission in February and November 2004 respectively for the older vacancies of the year upto 2001-02, which was much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme.

(ii) The Preliminary Tests were held prior to May 2005.

(iii) The requisition for Bihar Administrative Service pursuant to 47th Joint Competitive Examination were sought by the BPSC vide Letter No. Letter No. 430, dt. 06.05.2005, again much before the cutoff date of 01.09.2005 for the new contributory pension scheme.

(iv) The appointments against the older vacancies upto 2001-02 were covered under circular no. 502 dated 2-11-2002 of the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar), as is evident from Letter No. 10059, dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar)

(v) At no point of time it was mentioned that they (selected appointees under 46th and 47th Batch) despite being appointed against old vacancies will be governed by the new contributory pension scheme made applicable with effect from 1-9-2005.

A copy of the Letter No. 10059 dt. 10.11.2005 issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms, Government of Bihar (now GAD, Government of Bihar) is annexed as Annexure '03' to this writ petition.

7. That it is stated that in light of aforesaid, the older vacancies of the Bihar Administrative Service for the 46th and 47th Joint Competitive Examination were notified prior to the cutoff date of 01.09.2005 relevant for the new pension scheme and the process had begun under the old rules for the older vacancies and as such the old pension scheme shall be applicable for them.

8. That it is stated that under similar circumstances, some of the Drug Inspectors who were appointed after 1-9-2005 but pursuant to old advertisement and selection process had preferred a writ petition vide CWJC No. 10901 of 2006 claiming that they would not be covered by the resolution of government regarding applicability of new pension scheme to the effect that those appointed on 01.09.2005 and thereafter, shall have to be a member of newly contributory Pension fund scheme, and they claimed to be treated to have been appointed prior to dt. 01.09.2005 for pension purpose and the Hon'ble Court allowed the writ petition vide order dt. 03.08.2011 with observation that **it is well settled by now that old vacancies have to be governed by the old rules and the new rules coming into force after beginning of process of selection as per old rules, cannot be made applicable.**

9. That it is stated that the petitioner association has submitted a representation with details of facts and also the order of Hon'ble High Court dt. 03.08.2011passed in CWJC No. 10901 of 2006 before the General Administration Department, Government of Bihar vide its Memo No. 21 dt. 13.07.2021, however, no decision has been taken and no order has been passed and still the members of petitioner association belonging to 46th and 47th batch are being deprived of their legal entitlement.

A copy of the aforesaid representation contained in Memo No. 21, dt.13.07.2021 is annexed hereto as Annexure '04' to this writ petition.

10. That it is submitted that as the advertisements were brought before the cutoff date 01.09.2005 and the process of selection was initiated under old pension scheme under Bihar Pension Rules, the members of petitioner association under 46th and 47th batch, are entitled to old pension scheme.

11. That it is submitted that the delay in the process of selection on account of litigation or otherwise cannot be attributed and made detrimental for the members of 46th and 47th batch selected BASA officers and it was only due to the procedural requirements and other exigencies on part of the respondents.

12. That the action/inaction on the part of the respondents is unjust, unfair and arbitrary and as such the same is violative of Article-14 of the Constitution of India.

13. That it is submitted that the deprivation of 46th and 47th batch officers of petitioner Association from benefits of old pension scheme under Bihar Pension Rules is violative of Article 14, 16, 21 and 300A of the Constitution of India.

14. That it is stated that the petitioner has not preferred any other writ petition for the relief /s prayed herein.

15. That it is stated that the petitioner does not have alternative efficacious remedy than to prefer this writ petition.

It is, therefore, prayed that your lordships be graciously pleased to admit the application issue Rule NISI calling upon the respondents to show cause as to why the reliefs prayed for above may not be granted and upon return of the rule and on such cause as may be shown and after hearing the counsel for the parties be pleased to make the same absolute.

And / or

Pass such order/orders as your lordships may deem fit and proper in the given facts and circumstances of this case.

And for this the Petitioner shall ever pray.

9|9

12-9-18

9

AFFIDAVIT

I, Anil kumar aged about 56 Years, (Male), son of Late Er. Raja Ram Singh, resident of Village–Sareyan Basnat, P.O – Rampur Kesho Amnour P.S.– Taraiyan District –Saran, do hereby solemnly state and affirm as follows: -

1. That I am General Secretary of the Petitioner Association in this case and as such am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this writ petition have been drafted under my instructions and I have read the contents thereof which I have fully understood.
3. That it is stated that the averments made under Para 3, 6P, 9P and 14 .... are true to the best of my knowledge and under Para 4, 5, 6P, 7P, 8 and 9P .... are true to best of my information and the rest are by way of submission before the Hon'ble Court.
4. That the annexure/annexures are true copy of the original's copy.

Anil Kumar

महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

बिहार, पटना